सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।

-चाणक्य

हैलो सरकार

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉग ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोनः 0141-2202717
मोः 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-23 | अंक-260 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, रविवार 25 मई , 2025 | पृष्ठ-4 | मूल्यः 2.50

एसीबी ने पकड़ा बेल में रिश्वत का खेल

नई दिल्ली। दिल्ली में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल के बदले रिश्वत का मामला सामने आया है। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने न्याय और विधायी मामलों के विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर राउज एवेन्यू कोर्ट के एक स्पेशल जज और उनके कोर्ट स्टाफ (अहलमद) के खिलाफ जांच की अनुमति मांगी है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर देते हुए बताया है कि एसीबी ने आरोप लगाया है कि जज और कोर्ट स्टाफ ने आरोपियों को जमानत देने के बदले रिश्वत मांगी है।

पहले तो दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्याप्त सबूत का अभाव बताते हुए एसीबी को जज के खिलाफ जांच की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, एसीबी को जांच जारी रखने को कहा गया और आगे ठोस सबूत मिलने पर दोबारा संपर्क करने का सुझाव दिया गया। एसीबी ने 16 मई को कोर्ट स्टाफ पर एफआईआर दर्ज की। जिसके बाद 20 मई को संबंधित स्पेशल जज का ट्रांसफर कर दिया गया। इस मामले में अभी आधिकारिक तौर पर किसी पक्ष की ओर से कुछ नहीं कहा गया है।

क्या है केस?

2023 में एक एफआईआर अधिकारी पर फर्जी कंपनियों को गलत टैक्स रिफंड देने का आरोप लगा। एसीबी ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। जमानत की अर्जी पर सुनवाई लगातार टलती रही। 30 दिसंबर 2024 को एफआईआर अधिकारी के रिश्तेदार ने आरोप लगाया कि कोर्ट ने अधिकारियों से जमानत के बदले भारी रिश्वत मांगी और इनकार पर जमानत अटकाई। बाद में हाईकोर्ट से राहत मिली, लेकिन धमकियां दी गईं।

एसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, 20 जनवरी को एक और शिकायत मिली। जिसमें कोर्ट के कर्मचारी पर जमानत के बदले 15-20 लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था। एसीबी की जांच में आरोपों को समर्थन देने वाले ऑडियो साक्ष्य मिले। एफआईआर के बाद कोर्ट स्टाफ ने अग्रिम जमानत मांगी। एसीबी ने इसका विरोध करते हुए उन्हें मुख्य आरोपी बताया और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताई। 22 मई को कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी।

दिल्ली में जस्टिस वर्मा केस

14 मार्च 2025 को दिल्ली में होली की रात, हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास के स्टाफ क्वार्टर के पास स्थित एक स्टोर रूम में आग लग गई। आग बुझाने पहुंची दमकल टीम को वहां से कथित रूप से भारी मात्रा में अधजली नकदी की गड्डियां मिलीं। जस्टिस वर्मा उस समय दिल्ली से बाहर थे। घटना के बाद उन्होंने सफाई दी कि जिस कमरे में नकदी

मिली, वह उनके मुख्य निवास का हिस्सा नहीं है और वह स्टाफ व अन्य लोगों द्वारा उपयोग में लाया जाता था। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का निर्णय लिया और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उनके खिलाफ जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।

जस्टिस वर्मा ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिए गए स्पष्टीकरण में कहा यह कमरा सभी के लिए खुला था और इसका इस्तेमाल पुराना सामान, गार्डनिंग टूल्स, फर्नीचर आदि रखने के लिए होता था। यह मुख्य आवास से अलग स्थित है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति को आगे की कार्रवाई के लिए लिख दिया है।

अदालतों में सामने आते रहे हैं ऐसे मामले

जस्टिस निर्मल यादव केस - साल 2009 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज निर्मल यादव पर 15 लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगा था। एक वकील ने यह रकम गलती से किसी और जज के घर पहुंचा दी। जिससे पूरा मामला उजागर हुआ। यह केस सालों तक चर्चा में रहा।

जस्टिस दिनाकरण का इस्तीफा - मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीडी दिनाकरण साल 2009 से 2011 के बीच तमिलनाडु में अवैध भूमि अधिग्रहण और संपत्ति संचय के आरोप लगे। उनके खिलाफ 16 शिकायतें दर्ज हुईं और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी पदोन्नति रोक दी। बाद में दिनाकरण ने साल 2011 में इस्तीफा दे दिया।

आवाज उठाने वाले जज पर जब हुआ एक्शन - ऐसे ही कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस सीएस कर्णन ने साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद उनके खिलाफ अवमानना का मामला चला और उन्हें छह महीने की जेल हुई। यह भारतीय न्यायपालिका में एक अभूतपूर्व घटना थी।

एक अभूतपूर्व मामला भी आया सामने

इसके साथ ही साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर मुकदमों के गलत बंटवारे और न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगा। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार जजों ने सार्वजनिक तौर पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में जस्टिस चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकुर और कुरियन जोसेफ शामिल थे। विशेषज्ञों का मानना है कि इन घटनाओं ने एक बार फिर यह दिखाया है कि भारतीय न्यायपालिका में जवाबदेही और पारदर्शिता की गंभीर कमी है। जजों के खिलाफ कार्रवाई का एकमात्र संवैधानिक उपाय महाभियोग है, लेकिन आज तक किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी नहीं हो पाई है।

नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए CM भजनलाल

कोयला-पानी को लेकर PM मोदी से की डिमांड

जयपुर-राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने 'विकसित भारत-2047' के संकल्प की दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे ठोस प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने जल और ऊर्जा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से सहयोग की मांग करते हुए कई नई योजनाओं और उपलब्धियों को साझा किया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार आर्थिक समृद्धि, सतत विकास और समावेशी प्रगति को केंद्र में रखकर 'विकसित राजस्थान2047' विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, जिससे राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने रामजल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते को मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं राजस्थान की जल सुरक्षा और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हाल ही में चर्चित सैन्य अभियान 'ऑपरेशन सिंदूर' का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने आतंकवाद के खिलाफ सशक्त और निर्णायक रुख

अपनाया है। उन्होंने बीकानेर में अपने संबोधन के दौरान जनसाधारण में देखे गए राष्ट्रभक्ति के जज्बे को जीवन का भावुकतम क्षण बताया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3.25 लाख करोड़ के प्रस्तावों पर कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, एमएसएमई नीति 2024, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024, टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति 2025, लॉजिस्टिक नीति 2025 और डेटा सेंटर नीति 2025, जैसी नीतियों के माध्यम से रोजगार सृजन और समावेशी विकास की दिशा में ठोस पहल की है।

सीएम शर्मा ने बताया कि राज्य में अटल इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है जिससे युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक 67 हजार युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी हैं, और 1.87 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ने अक्षय ऊर्जा में 10 हजार मेगावाट की वृद्धि दर्ज की है। सौर ऊर्जा और कुल अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान आज देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने पीएम कुसुम योजना के तहत अतिरिक्त 5 हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता और 5 हजार मेगावाट आवर बैटरी स्टोरेज की मांग केंद्र से की।

सीएम शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम 2025 ला रही है, जिसके तहत रिसाइक्लिंग और रीयूज क्षेत्र में 2 करोड़ रुपये तक अनुदान और ऋण पर 0.5त्न अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

सवाईमाधोपुर रिश्वत प्रकरण में जिला परिवहन अधिकारी पुन्याराम मीणा गिरफ्तार, एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई

जयपुर। राजस्थान में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही मुहिम के तहत एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सवाईमाधोपुर रिश्वत प्रकरण में अनुसंधान के दौरान संलिप्तता पाए जाने पर जिला परिवहन अधिकारी पुन्याराम मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले इसी मामले में एसीबी के तत्कालीन प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार शर्मा और दो दलालों को 19 मई को गिरफ्तार किया गया था। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर इकाई द्वारा इस प्रकरण में लगातार कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर अब परिवहन विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।

सीबीआई फाटक, जगतपुरा से आरोपी की गिरफ्तारी

ब्यूरो के उपमहानिरीक्षक पुलिस राजेश सिंह के पर्यवेक्षण में एसीबी जयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अनुसंधान अधिकारी) विशनाराम के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक राजकुमार शर्मा की टीम ने आज आरोपी पुन्याराम मीणा को जयपुर के सीबीआई फाटक, जगतपुरा इलाके से दस्तयाब किया। प्रारंभिक पूछताछ और गहन अनुसंधान के उपरांत उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए गए, जिसके

आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ और आगे की कार्रवाई जारी

ब्यूरो अधिकारियों के अनुसार, आरोपी पुन्याराम मीणा से गहन पूछताछ की जा रही है, जिसमें यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस पूरे भ्रष्टाचार चक्र में और किन-किन अधिकारियों की भूमिका रही है। माना जा रहा है कि यह रिश्वत प्रकरण एक संगठित नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें एसीबी के ही कुछ अधिकारी, परिवहन विभाग के उच्चाधिकारी और दलाल वर्ग शामिल हो सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार, इस मामले में फंड ट्रांजेक्शन, सरकारी कार्यों में देरी के बदले रिश्वत की मांग, वाहन पंजीकरण और लाइसेंस प्रक्रिया में अवैध शुल्क वसूली जैसे मामलों की भी जांच की जा रही है।

पृष्ठभूमि-क्या है सवाई माधोपुर रिश्वत प्रकरण?

19 मई 2025 को सवाईमाधोपुर में एसीबी की एक टीम ने भ्रष्टाचार के एक मामले में तत्कालीन एसीबी प्रभारी एएसपी सुरेन्द्र कुमार शर्मा और दो दलालों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोप था कि सरकारी कार्यों में सहूलियत देने और फाइलों की स्वीकृति के बदले घूस ली जा रही थी। इस कार्रवाई ने पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी थी।

इसके बाद जयपुर स्थित मुख्यालय ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में ही परिवहन विभाग के अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके चलते पुन्याराम मीणा पर शिकंजा कसा गया।

राजस्थान में एसीबी की सख्त कार्रवाई जारी

राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के बाद एसीबी की सक्रियता में लगातार इज़ाफा हुआ है। पिछले एक वर्ष में ब्यूरो द्वारा विभिन्न विभागों के 100 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक मंचों पर भी साफ कहा गया है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी स्तर पर क्यों न हो।

इस मामले को लेकर अब नजरें उस रिपोर्ट पर टिकी हैं जो एसीबी आगामी सप्ताह में सरकार को सौंपेगी। माना जा रहा है कि रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। यदि अन्य विभागों की संलिप्तता भी पाई जाती है, तो आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं।

एसीबी सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही फर्जी बिलिंग, अवैध परमिट, दलाल नेटवर्क और बैंक ट्रांजेक्शन की गहन जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की जाएगी।

भजनलाल सरकार के सारे दावे खोखले, जनता बेहाल-अशोक गहलोत

जयपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की तरफ से निवेश के दावे किए जाने को शनिवार को खोखला बताया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री जी यह सब अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनसे कहलवाया जा रहा है। वह जो कुछ भी बोल रहे हैं, उसकी सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है।

उन्होंने प्रदेश में लोगों को हो रही पेयजल समस्या का भी जिक्र किया। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन, सरकार का दोहरा पैमाना देखिए कि एक तरफ जहां ये लोग सार्वजनिक मंचों पर बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है?

उन्होंने मनरेगा श्रमिकों पर कहा कि मौजूदा समय में उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन, प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन को चाहिए कि श्रमिकों से एक घंटा कम काम

कराया जाए। हमारे श्रमिकों के ऊपर काम का अत्यधिक बोझ डाला जा रहा है, जिससे उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि एक सोची-समझी साजिश के तहत हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। उन पर राजनीतिक हमले करके हमारे हौसले को पस्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारा हौसला पस्त नहीं होगा।

उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई को भाजपा की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि आज से 90 साल पहले हमने इस अखबार को शुरू किया था। इसके बाद यह किसी कारणवश बंद हो गया, लेकिन अब हम इसे फिर से शुरू करने जा रहे हैं। जिससे भाजपा परेशान हो चुकी है। भाजपा को इस बात का डर है कि अगर नेशनल हेराल्ड को फिर से शुरू किया गया, तो कांग्रेस खुलकर अपने विचार प्रकट करेगी, जिससे उन्हें समस्या होगी।

उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' के संबंध में राहुल गांधी के सवालों की आलोचना किए जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। अगर वे सवाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर वे सवाल नहीं करेंगे, तो कल को जनता पूछेगी कि आप तो विपक्ष के नेता थे, लेकिन आपने आज तक कोई सवाल ही नहीं किया। आपने अपनी भूमिका का निर्वहन ढंग से किया ही नहीं।

उन्होंने कहा कि आप इतिहास देख लीजिए। अमेरिका ने कभी हमारा साथ नहीं दिया। जब कारगिल युद्ध हुआ था, तब भी उसने हमारा साथ नहीं दिया था। ऐसी स्थिति में भारत को हिम्मत दिखानी चाहिए और उसे अमेरिका को दो टूक जवाब देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि आखिर किस हैसियत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर का ऐलान करते हैं। सीजफायर का ऐलान भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी सहमति से होना चाहिए था। लेकिन, ऐसा हुआ नहीं, अमेरिका ने इस मामले में दखल दे दिया।

महिलाओं को एक भाषा में, एक स्वर में और एक उद्देश्य के लिए बोलना चाहिए- दीया कुमारी

जयपुर। दुनिया भर में महिलाओं को एक जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि महिलाएं एकजुट होकर, एक स्वर और एक भाषा में बोलें, तो कोई भी ताकत उन्हें किसी भी क्षेत्र में अपने लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती। यह बात राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने आज जयपुर में आयोजित आईडब्ल्यूएन राजस्थान वुमन लीडरशिप समिट 2025 के छठे संस्करण के दौरान %सेलिब्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप% थीम पर एक सत्र में विशेष संबोधन के दौरान कही।

समिट का आयोजन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) - इंडियन वुमन नेटवर्क (आईडब्ल्यूएन), राजस्थान चैप्टर द्वारा किया गया था।

दीया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला सशक्तिकरण की पहलों की सराहना की, जैसे %बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ% और संसद में महिलाओं को 33त्न आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय। उन्होंने महिलाओं से आग्रह किया कि वे समाज में बदलाव की प्रेरक शक्ति बनें और वंचित वर्ग की महिलाओं को सरकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ दिलाने में मदद करें।

उप मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के प्रयासों के लिए अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने निजी अनुभव साझा करते हुए कहा कि एक सैन्य परिवार की बेटी होने के नाते, वह सेना के बलिदान और सेवा भाव को अच्छे से समझती हैं। इसके साथ ही, उन्होंने राजस्थान के विकास में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और सीआईआई की सक्रिय भागीदारी के साथ राइजिंग राजस्थान पहल को विकास का एक सफल मॉडल बताया।

एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिण-पश्चिमी कमान, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की अहम भूमिका पर जोर दिया, खासकर हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर में उनके नेतृत्व को उजागर करते हुए। विशेष रूप से, भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय वायु सेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस ऑपरेशन की आधिकारिक ब्रीफिंग का नेतृत्व किया, जो भारत की सैन्य संचार इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनका नेतृत्व न केवल भारत की सैन्य ताकत को दर्शाता है, बल्कि रक्षा क्षेत्र में लिंग समानता के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है, जो यूनिफॉर्म में आने वाली पीढ़ी की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, डॉ. नेहा गिरी ने अपने धौलपुर कलेक्टर पद के दौरान छुआछूत खत्म करने के अपने प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने याद करते हुए बताया कैसे उन्होंने कार्यस्थल पर एक दलित महिला द्वारा दिया गया पानी पीकर जातिगत बाधाओं को तोड़ा। उन्होंने समाज में सोच बदलने की ज़रूरी आवश्यकता पर ज़ोर दिया, जिसमें पुरुष घर के काम में बराबर की जिम्मेदारी लें और बच्चों को छोटी उम्र से ही समानता और समावेशन का महत्व समझाया जाए।

राजस्थान के मदरसों में पढ़ाया जाएगा 'ऑपरेशन सिंदूर', कर्नल सोफिया बनेंगी बेटियों की प्रेरणा

जयपुर। राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मदरसों में अब भारतीय सेना के शौर्य गाथा 'ऑपरेशन सिंदूर' को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य मदरसों में पढ़ने वाली बच्चियों को देशभक्ति, साहस और सैन्य सेवा के प्रति जागरूक और प्रेरित करना है।

सेना की नायिकाओं से मिलेगी प्रेरणा

एमडी चोपदार ने जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान के लगभग 37 मदरसों में 2 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यहां राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हम इसमें 'ऑपरेशन सिंदूर' को शामिल करेंगे, विशेष रूप से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की भूमिका पर फोकस किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इन महिला सैन्य अधिकारियों के योगदान को जानकर छात्राएं प्रेरित होंगी और आगे चलकर भारतीय सेना में सेवा देने का सपना देख सकेंगी।

शिक्षा के साथ राष्ट्रीय चेतना का समावेश

मदरसा बोर्ड का यह निर्णय सिर्फ एक पाठ्य विषय जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों में राष्ट्रप्रेम, सेवा भावना और आत्मबल बढ़ाने का प्रयास है। चोपदार ने बताया कि सभी मदरसों में विशेष मीटिंग आयोजित कर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा की जाएगी।

क्यों जनता भ्रष्टाचार का अनचाहा भार ढ़ोये?

सरकार गरीबों के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन बड़ा स्थापित तथ्य है कि अधिकतर सरकारी योजनाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पातीं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। इस योजना की शुरुआत इस मकसद से की गई थी कि गरीब परिवारों को साल में कम से कम सौ दिन रोजगार मिल सकेगा और वे अपना भरण-पोषण कर सकेंगे मगर शुरुआती वर्षों में ही इसमें भ्रष्टाचार उजागर होने लगे थे। फर्जी नाम दर्ज कर काम देने की बड़ी चालबाजियां सामने आई थीं।

लेखक - ललित गर्ग

विभिन्न राजनीतिक दलों, विभिन्न प्रांतों की सरकारों, विभिन्न गरीब कल्याण की योजनाओं, न्यायिक क्षेत्र एवं उच्च जांच एजेंसियों में भ्रष्टाचार की बढ़ती स्थितियां गंभीर चिन्ता का विषय है। ऐसा लगता है आज हम जीवन नहीं, राजनीतिक, न्यायिक एवं प्रशासनिक मजबूरियां जी रहे हैं। ऐसा भी लगता है न्याय, राजनीति एवं प्रशासन की सार्थकता एवं साफ-सुथरा उद्देश्य नहीं रहा, स्वार्थपूर्ति का जरिया बन गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा एक असामान्य घटनाक्रम के तहत भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के तीन अधिकारियों को उसी सीबीआई की हिरासत में भेज देना न केवल चिन्ताजनक एवं शर्मनाक है बल्कि विडम्बनापूर्ण है। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ केन्द्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का बुगल बजाय हुए है, जिससे राजनीति में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का नया सूरज उदित होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सीबीआई जैसी जांच एजेन्सी में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होना इस सूरज को उदित होने से पहले ही अंधेरा की ओट में ले रहा है। इससे भी बड़ी त्रासद एवं निराशाजनक है गुजरात में 71 करोड़ रुपये के मनरेगा घोटाले में मंत्री बच्चू भाई खाबड़ के दो बेटों का गिरफ्तार होना। राजनीति एवं कार्यपालिका के साथ न्याय पालिका के क्षेत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में कथित तौर पर नकदी मिलना भ्रष्टाचार के सर्वत्र व्याप्त होने को दर्शा रहा है। जनता कब तक भ्रष्टाचार का अनचाहा भार ढ़ोती रहेगी। कैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भ्रष्टाचारमुक्त आदर्श राष्ट्र-निर्माण के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे? कैसे आजादी के अमृत काल में ईमानदार राष्ट्र बना पायेंगे? न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने 25 अप्रैल को सीबीआई के तीन अधिकारियों के भ्रष्टता पर अपने आदेश में कहा कि यह सीबीआई, ईडी और ऐसे अन्य विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अनूठा मामला है, जिसने हमारी कार्यपालिका और जांच तंत्र की पूरी संरचना को हिलाकर रख दिया है। इन एजेंसियों का प्राथमिक कर्तव्य अपराध की जांच करना और भ्रष्टाचार के दोषियों को सजा दिलाना है। लेकिन इन उच्च जांच एजेन्सियों के आला अधिकारी ही भ्रष्ट हो तो दूसरों के भ्रष्टाचार मामलों में निष्पक्ष एवं तीक्ष्ण जांच की उम्मीद कैसे संभव है? सीबीआई-भ्रष्टाचार एकमात्र मामला नहीं है, बल्कि यह विभिन्न विभागों के अधिकारियों के बीच एक 'बड़ी साजिश' को दर्शाता है, जो अनुचित लाभ या प्रभाव डालने समेत इन विभागों के कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए रिश्वत के मामले को दर्शाता है। अब सर्वोच्च न्यायालय के जज भी ऐसे मामलों में लिप्त हो तो समस्या की गंभीरता को सहज ही समझा जा सकता है। निश्चित ही भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में जस्टिस वर्मा केस एक दुर्लभ एवं संवेदनशील मौका है। अब इसकी वजह से न्यायपालिका की गरिमा को ठेस न पहुंचे और जनता का भरोसा बना रहे, इसके लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मामले से जुड़ी जानकारियों को देश से साझा किया। साथ ही, उनकी पहल पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी सार्वजनिक किया। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर किया गया और जांच कमिटी बनाकर उसकी रिपोर्ट सरकार व राष्ट्रपति के पास भेजकर महाभियोग की सिफारिश कर दी गई है। यहां से अब गेंद सरकार और संसद के पाले में है। महाभियोग ही एकमात्र तरीका है, जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मौजूदा जजों को हटाया जा सकता है। लेकिन, आजाद भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले, भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग चला था, लेकिन लोकसभा में वोटिंग से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया यानी वहां भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। अब अगर जस्टिस वर्मा का यह मामला महाभियोग तक पहुंचता है, तो वहां भी एक लंबी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखते हुए प्रक्रिया की जटिलता को कम किया जा सकता है? ताकि जजों के भ्रष्टाचार की उचित सजा उनको मिल सके, ऐसी प्रक्रिया से ही न्यायपालिका बिना किसी डर, दबाव या लालच के अपना कर्तव्य भी निभा सके। भ्रष्टाचार की परतें अपराधियों एवं भ्रष्ट लोगों को बचाने तक ही सीमित नहीं है, अब तो यह गरीबों का निवाला भी छीन रही है। सरकार गरीबों के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन बड़ा स्थापित तथ्य है कि अधिकतर सरकारी योजनाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पातीं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। इस योजना की शुरुआत इस मकसद से की गई थी कि गरीब परिवारों को साल में कम से कम सौ दिन रोजगार मिल सकेगा और वे अपना भरण-पोषण कर सकेंगे मगर शुरुआती वर्षों में ही इसमें भ्रष्टाचार उजागर होने लगे थे। फर्जी नाम दर्ज कर काम देने की बड़ी चालबाजियां सामने आई थीं। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का ताना-बाना संबंधित महकमों में ही बुना जाता है। इसी का त्रासद उदाहरण गुजरात में मनरेगा के तहत फर्जी तरीके से कार्य निष्पादन के दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की रकम भुना लेने का है। पुलिस ने इस मामले में अब तक ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें सड़क, बांध, पुलिया आदि निर्माण के लिए सामग्री मुहैया कराने का ठेका दिया गया था। इस घोटाले ने इसलिए तूल पकड़ा और राजनीतिक रंग ले लिया है कि इसमें वहां के पंचायत और कृषि राज्यमंत्री के दो बेटों को भी गिरफ्तार किया गया है। गुजरात ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी मनरेगा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के किस्से उजागर हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी मनरेगा भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। जिले के कई ब्लॉक में मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है। फर्जी हाजिरी और फोटो घोटाले से हर दिन लाखों रुपये की लूट हो रही है। एक ही फोटो को बार-बार इस्तेमाल करके लाखों रुपये निकाले जा रहे हैं। गुजरात में मंत्री के बेटों के द्वारा मनरेगा लूट एवं भ्रष्टाचार अधिक परेशान करने वाला एवं चिन्ता में डालने वाला है। नेता, मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारी अच्छे-बुरे, उपयोगी-अनुपयोगी का फर्क नहीं कर पा रहे हैं। मार्गदर्शक यानि नेता शब्द कितना पवित्र व अर्थपूर्ण था पर अब नेता खलनायक बन गया है। नेतृत्व व्यवसायी एवं भ्रष्टाचारी बन गया। आज नेता शब्द एक गाली है। जबकि नेता तो पिता का पर्याय था। उसे पिता का किरदार निभाना चाहिए था। पिता केवल वही नहीं होता जो जन्म का हेतु बनता है अपितु वह भी होता है, जो अनुशासन सिखाता है, ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है, विकास की राह दिखाता है। आगे बढ़ने का मार्गदर्शक बनता है। अब तक आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल आदि राजनीतिक दलों में ही भ्रष्टाचार के किस्से सामने आ रहे थे, अब भाजपा नेताओं एवं मंत्रियों पर भी ऐसे आरोप लगना ज्यादा चिन्ताजनक है। प्रश्न भाजपा का ही नहीं है, भ्रष्टाचार जहां भी हो, उसके खिलाफ बिना किसी पक्षपात के कार्रवाई की जानी चाहिए। भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है, नया भारत एवं सशक्त भारत को निर्मित करने के लिये तत्पर है तो उसकी पार्टी के भीतर भी यदि भ्रष्टाचार है तो उसकी सफाई ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी दल के नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का बुगल बजाय हुए हैं तो यह नये भारत, सशक्त भारत, ईमानदार भारत बनाने की सार्थक पहल है। राजनीतिज्ञों, जजों, प्रशासनिक अधिकारियों की साख गिरेगी, तो राष्ट्र की साख बचाना भी आसान नहीं होगा। चहुंओर पसरे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से विकास के दावों का विद्रूप रूप ही सामने आता है। हमारे पास कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं राजनीति ही समाज की बेहतरी का भरोसेमंद रास्ता है और इसकी साख गिराने वाले कारणों में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के बाद तीसरा नंबर कीचड़ उछाल राजनीति का भी है, जिसमें गलत को गलत नहीं माना जाता। ये तीनों ही ऐसे औजार है, जो देश को तबाही की ओर ले जाते हैं।

अपराधीकरण और भ्रष्टाचार का मसला काफी गहरा है और इससे खिलाफ आरपार की लड़ाई के लिए काफी कठोरता, निष्पक्षता, वक्त और ऊर्जा की जरूरत है, सख्त कदम उठाने की अपेक्षा है। ऐसी ही उम्मीदभरी एवं भ्रष्टाचार-निरोधक कार्रवाई से भारत का लोकतंत्र समृद्ध हो सकेगा।

(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार) (यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

पुल बने भाषा

इसमें दो राय नहीं कि भाषाई विविधता रंग-बिरंगे फूलों की तरह भारत की खूबसूरती की वाहक है। वही यह विविधता देश की सांस्कृतिक समृद्धि का आधार भी है। यह विडंबना ही है कि राजनीतिक लाभ के लिये क्षेत्रीय भाषा के गौरव के नाम पर हिंदी विरोध का मोर्चा अकसर खोला जाता है। निस्संदेह समय-समय पर उभरने वाले विवाद क्षेत्रीय गर्व और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियों को ही उजागर करते हैं। कुछ समय पहले ऐसे ही विवाद में मराठी को व्यवहार में न अपनाने के आरोप लगाकर एक अधिकारी को थप्पड़ मारने का विवाद सामने आया था। कालांतर भाजपा शासित राज्य में मराठी की अनिवार्यता कामकाज में लागू की गई थी। अब ताजा विवाद कर्नाटक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक प्रबंधक के कन्नड़ में बात करने से इनकार करने पर उठा है। जिसका कहना था कि वह हिंदी भाषी है और हिंदी में वार्तालाप करेगा। इस प्रकरण में अधिकारी का तबादला व खासा विवाद हुआ। स्वाभाविक रूप से क्षेत्रीय भाषा की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल खासे सक्रिय हुए। इस बीच जन सेवा में भाषाई संवेदनशीलता के प्रशिक्षण की मांग भी उठी। वैसे भी केंद्रीय सेवाओं के रूप में काम करने वाले विभागों व बैंक आदि के कर्मचारियों व अधिकारियों के विभिन्न राज्यों में अकसर तबादले होते रहते हैं। यह संभव भी नहीं कि हर व्यक्ति हर राज्य की भाषा बोल सके, लेकिन सीधे तौर पर जन-सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य की स्थानीय भाषा का ही उपयोग उपभोक्ताओं से सहज संवाद के लिये करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बेंगलुरू में एक तकनीकी पेशेवर को हिंदी में बोलने के कारण पार्किंग की सुविधा से वंचित कर दिया गया। इस घटना ने गैर हिंदी भाषी इलाकों में भाषायी सहिष्णुता की बहस को नये सिरे से खड़ा किया। निश्चित रूप से दोनों ही घटनाएं भाषाई व सांस्कृतिक एकता के लिये चुनौती पेश करती हैं। जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि ये घटनाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के त्रि-भाषा फार्मूले की पृष्ठभूमि में हुई हैं। दरअसल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों को तीन भाषाएं सीखने की सलाह दी गई है। जिसमें कम से कम दो भारत की मूल भाषाएं होनी चाहिए। हालांकि, इस शैक्षिक नीति का मकसद बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है,लेकिन तमिलनाडु में इस नीति का प्रतिरोध सामने आया है। राजनीतिक दल इसे हिंदी थोपने और अपनी भाषाई पहचान के लिये खतरा बता रहे हैं। तमिलनाडु में हिंदी को लेकर विरोध की राजनीति का पुराना इतिहास रहा है। खासकर तब से जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की कवायद शुरू हुई थी। हालांकि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लचीलेपन के साथ इस बात पर जोर देती रही है कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। इसके साथ यह भी कि भाषाओं के चयन का मुद्दा राज्य, क्षेत्रों और छात्रों पर छोड़ दिया जाएगा। वहीं कतिपय राजनीतिक दल आरोप लगाते रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा का व्यावहारिक क्रियान्वयन एक विवादस्पद मुद्दा है। बहरहाल, इस मुद्दे पर क्षेत्रीय भाषाओं पर इसके प्रभाव और हिंदी के कथित प्रभुत्व को लेकर बहस चल रही है। बहरहाल, इस तरह के विवादों से आगे बढ़ने के लिये आपसी सम्मान और समझ का माहौल बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। सार्वजनिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनकी सेवाएं स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही कर्मचारियों व अधिकारियों को सांस्कृतिक और भाषाई संवेदनशीलता में प्रशिक्षित किया जाए। निस्संदेह, शैक्षिक नीतियों को पूरे लचीलेपन के साथ लागू किया जाना चाहिए। जिसमें बहुभाषी दक्षता को बढ़ावा देते हुए क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान किया जाना चाहिए।

कोरोना की दस्तक पर सजगता जरूरी

कोविड का नया वैरिएंट/ ऋतुपर्ण दवे

देशभर के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की भी जिम्मेदारी है कि वे सभी पर्याप्त इंतजाम रखें। जरा सा संदेह होने पर चिकित्सकीय परामर्श में कोताही न बरतें। अच्छा हो कि अभी से सचेत हो जाएं। देश-दुनिया पर कोरोना का संकट एक बार फिर मंडरा रहा है। वैसे देश में प्रभावितों की संख्या मामूली है। 19 मई तक आधिकारिक तौर पर 257 मामले थे। अभी बीते सप्ताह के ताजे आंकड़ों के अनुसार संख्या कम जरूर है लेकिन सच्चाई भी है कि मामले या तो समझ नहीं आ रहे या दर्ज नहीं हो रहे हैं। बीते सप्ताह केरल में 69, महाराष्ट्र में 44 और तमिलनाडु में 34 मामले दर्ज हुए। लेकिन शेष एशिया में जिस तरह से कोविड के मामले दर्ज हो रहे हैं, वे चिंता बढ़ाते दिख रहे हैं। हांगकांग और सिंगापुर में यह तेजी से फैल रहा है। अभी नया वैरिएंट जेएन-1 का प्रकोप जारी है। यह पहली बार अगस्त, 2023 में मिला था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे दिसंबर, 2023 में ही 'वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट' घोषित कर साफ किया था कि यह ओमिक्रॉन बीए 2.86 का वंशज है। इसमें 30 के लगभग म्यूटेशन पाए गए जिनमें एलएफ7 और एनबी1.8 की संख्या ज्यादा थी। कोरोना की यह नई लहर साउथ-ईस्ट एशिया में ज्यादा असर दिखा रही है। सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड जैसे देशों में कोविड के मामले बहुत ही तेजी से बढ़े हैं। अकेले सिंगापुर में मई की शुरुआत में 14,200 से ज्यादा नए मामले आए। इन जगहों पर भी जेएन1 और उसके उप-वैरिएंट ज्यादा मिल रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इन देशों में बढ़ते मामलों का कारण वहां लोगों के शरीर में एंटीबॉडी का कम हो जाना भी है। भारत में भी ऐसी संभावना से इंकार नहीं है। तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में धीरे ही सही, इसका बढ़ना अच्छा संकेत नहीं है।

बीते 18 मई को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रैविस हेड कोरोना संक्रमित हुए तो दूसरे ही दिन बिग बॉस फेम शिल्पा शिरोडकर भी शिकार हो गईं। इतना तो समझ आ गया है कि सिंगापुर अब नया हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है। सप्ताहभर में ही संक्रमण के मामलों में 28 फीसदी की वृद्धि चिंताजनक है। चीन से छन-छनकर जो निकल रहा है वहां भी बीते एक महीने में कोरोना मामलों में काफी तेजी आई है। लेकिन चीन से जितने वैरिएंट सामने आए, उसने दुनिया में कैसा विनाश मचाया था, सबने देखा।

इस बार संक्रमित होने वाले अधिकतर लोग वे हैं जो कोमोरबिडिटी यानी सह-रुग्णता वाली स्थिति में हैं। इसमें प्रभावितों को एक ही समय में एक से अधिक बीमारियां होती हैं। कुछ सामान्य जोखिम कारक होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्थितियों से उत्पन्न लक्षणों या उसके उपचारों के कारण होते हैं। अभी ज्यादातर लक्षण, कोमोरबिडिटी या फिर 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में दिख रहे हैं। स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए अधिकारियों ने डॉक्टर की सलाह पर अपडेटेड वैक्सीन लेने की सलाह दी है। उच्च जोखिम वाले बुजुर्गों, कोमोरबिडिटी के शिकार को पहले से ही सालाना कोविड-19 वैक्सीन लेने की सलाह दी जाती रही है। मुंबई के एक अस्पताल में दो मरीजों की मौत के बाद भ्रम की स्थिति बनी है। अस्पताल ने इन्हें गंभीर बीमारियों से हुई मौत बताया जिसका कोविड-19 से कोई संबंध नहीं था। अस्पताल का कहना है कि मौतें कोविड-19 से नहीं, बल्कि हाइपोकैल्सीमिक दौरे और कैंसर के साथ नेफोटिक सिंड्रोम जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हुई हैं। लेकिन चर्चा है कि दोनों मृतकों में कोविड के लक्षण थे। लगता नहीं कि ऐसी ऊहापोह वाली स्थितियों से कोविड को लेकर फिर पहले जैसा भ्रम फैलेगा? भारत में फिर से कोरोना वायरस के मामले धीरे-धीरे बढ़ने लगे हैं।

हांगकांग के स्वास्थ्य अधिकारी अल्बर्ट अउ का बयान चिंताजनक है जिसमें उन्होंने माना कि कोरोना वायरस के मामले वहां तेजी से बढ़ रहे हैं। सांस लेने की तकलीफ वाले मरीजों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने की संख्या अभी साल के महज पांचवें महीने में ही उच्च स्तर पर पहुंच गई है। जबकि चीन में श्वास संबंधी

बीमारियों की जांच करवाने वाले मरीजों में कोविड वायरस पाए जाने के मामले दोगुने होना चिंताजनक है। लोगों को बूस्टर शॉट लेने की सलाह दी गई है। साथ ही चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों के मुताबिक, कोविड की लहर तेज भी हो सकती है।

साउथ-ईस्ट एशिया के हालात देखते हुए भारत भी सतर्क है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण, आपदा प्रबंधन सेल, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोविड के पुष्ट मामलों की मौजूदा संख्या 257 है। देश की आबादी के दृष्टिगत यह बहुत कम है। अस्पतालों को इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारियों और श्वसन संक्रमण के गंभीर मामलों की निगरानी करने के लिए कहा गया है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति पर बारीकी से निगरानी रख हुए है।

देशभर के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की भी जिम्मेदारी है कि वे सभी पर्याप्त इंतजाम रखें। जरा-सा संदेह होने पर चिकित्सकीय परामर्श में कोताही न बरतें। अच्छा हो कि अभी से सचेत हो जाएं।

(चिंतन-मनन)

संतोष का मार्ग

चिंतन मनन

एक ऋषि अपने शिष्य कपिल के साथ श्रावस्ती नरेश के पास गए। ऋषि से मिलकर नरेश प्रसन्न हुए और उनके आदर-सत्कार में लग गए। इधर कपिल एक सेविका के रूप पर मुग्ध हो गया। उस सेविका ने कपिल से विवाह करने से पहले महंगे कपड़े और गहने मांगे। कपिल यह सब देने में असमर्थ था। सेविका ने इसकी व्यवस्था का तरीका बताते हुए कहा कि जो श्रावस्ती नरेश का प्रातःकाल सर्वप्रथम अभिवादन करता है, उसे वे दो स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करते है। कपिल रात बीतने के पहले ही नरेश के शयनकक्ष में घुसने लगा मगर चोर समझकर द्वारपालों ने उसे पकड़ लिया। नरेश के सामने उसने सब बातें सच-सच कह दीं। उसके भोलेपन पर प्रसन्न हो नरेश ने उसकी मुंहमांगी चीज देने का वचन दिया।

कपिल ने एक दिन का समय मांगा। सोचने लगा, दो स्वर्ण मुद्राएं तो कम हैं, क्यों न सौ मांग लूं, पर वे भी कितने दिन चलेंगी। उसने पूरा राज्य ही मांग लिया। श्रावस्ती नरेश निःसंतान थे, उन्हें योग्य व्यक्ति की तलाश भी थी। उन्हें कपिल योग्य लगा। वह बोले- तुमने मेरा उद्धार कर दिया। मैं तृष्णा रूपी सर्पिणी के पाश से छूट गया। यह सुनकर कपिल का विवेक जाग्रत हो गया।

वह बोला- महाराज, आप जिस दलदल से निकलना चाहते हैं, उसी में मैं गिरना नहीं चाहता। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह ऋषि के पास गया और उनसे सब कुछ कह डाला। ऋषि बोले- कामनाओं का कहीं अंत नहीं होता, इसलिए जितना अपने परिश्रम और ईश्वर कृपा से मिल जाए, उसी में प्रसन्न व संतुष्ट रहना चाहिए।

विचार मंथन

संरक्षित धन का मूल्यांकन कर, रिजर्व बैंक से डिविडेंड वसूल कर रही है, सरकार?

(लेखक- सनत जैन)

केंद्र सरकार ने एक बार फिर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से 2.69 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक डिविडेंड वसूल किया है। यह अब तक की सबसे बडी डिविडेंड की राशि है जिसका ट्रांसफर रिजर्व बैंक सरकार को कर रहा है। रिजर्व बैंक में जमा सोने का भंडार और विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ जाने से सरकार ने इसे रिजर्व बैंक का मुनाफा मान लिया है। सवाल यह है, यह डिविडेंड रिजर्व बैंक का असल लाभ का नतीजा है,या बाजार में कीमत बढ़ने से सोने एवं विदेशी मुद्रा भंडार का जो मूल्यांकन बढा है। बाजार में सोने और डॉलर की कीमत चढ़ती और उतरती रहती है। आज जो मुनाफा दिख रहा है। कल वह घाटे में भी बदल सकता है। सरकार ने मूल्य वृद्धि को मुनाफा मानकर अपना डिवीडेंड रिजर्व बैंक से ले लिया। भविष्य में यदि घाटा होगा, तो नुकसान रिजर्व बैंक का होगा। रिजर्व बैंक कोई कंपनी नहीं है। रिजर्व बैंक कोई व्यापार भी नहीं करता है। एक नियामक संस्था है, उसके पास जो संपत्तियाँ हैं। जैसे विदेशी मुद्रा भंडार, सोने का भंडार वह किसी व्यापार या विक्रय की कमाई से नहीं आया है। बाजार में मूल्य परिवर्तन से उसका मूल्यांकन साख के रूप में होता है। रिजर्व बैंक में जमा सोना और विदेशी मुद्रा भंडार से अंतरराष्ट्रीय साख बनती है। उसी साख के आधार पर वैश्विक संस्थाओं द्वारा रिजर्व बैंक की आर्थिक स्थिति का मूल्याकन किया जाता है। रिजर्व बैंक में जमा गोल्ड रिज़र्व की वैल्यू पिछले साल 80 बिलियन थी। जो इस साल बढ़कर 100 बिलियन हो गई। सोने की सिर्फ कागज पर कीमत बढ़ी है। सोने की बिक्री नहीं हुई है। रिजर्व बैंक में जमा डॉलर की वैल्यू बढ़ी है। रुपये के मुकाबले 78-79 से बढ़कर 85-86 रुपया डॉलर का मूल्य हो गया है। जिससे विदेशी मुद्रा भंडार की वैल्यू कागज़ पर बढ़ी है। इस बढ़े हुए मूल्य को केंद्र सरकार ने मुनाफा मानकर रिजर्व बैंक से डिविडेंड मांग लिया। वास्तव में रिज़र्व बैंक की बैलेंस शीट का वर्तमान प्रचलित मूल्य पर यह री-वैल्यूएशन है। जिसे सरकार मुनाफा मान रही है। रिजर्व बैंक का जमा यह फंड भविष्य के संकटों, मुद्रा स्थिरता और बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा के लिए रिजर्व बैंक के पास अभी तक सुरक्षित रहता आया है। केंद्र सरकार की यह प्रवृत्ति चिंताजनक है। केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से डिविडेंड लेने के नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के इस नियम के कारण रिजर्व बैंक की स्वतंत्रता और दीर्घकालिक आर्थिक स्थितियों के संतुलन की स्थिरता पर असर पड़ना तय है। सोचने की बात यह है, जब सरकार रिजर्व बैंक से इतना बड़ा डिविडेंड ले रही है। ऐसी स्थिति में पेट्रोल-डीज़ल पर करों के ज़रिए जनता से 4 लाख करोड़ रुपये की वसूली क्यों की जा रही है। कागज़ी लाभ को मुनाफा कब से माना जाने लगा। आम आदमियों के ऊपर भी क्या इसी तरीके से लाभ मानकर टैक्स लगाया जा सकता है। पिछले एक दशक से केंद्र सरकार टैक्स के रूप में भारी राजस्व एकत्रित कर रही है ऐसी स्थिति में क्या आम नागरिक को टैक्स से राहत नहीं मिलनी चाहिए। सरकार को, रिजर्व बैंक की जो आय दिख रही है। वह काल्पनिक मुनाफा है। मूल्य गिरने पर इसके पीछे का घाटा रिजर्व बैंक का जोखिम है। वित्तीय स्वायत्तता, मौद्रिक नीति की निष्पक्षता पर जनता का भरोसा कैसे रिजर्व बैंक पर बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के खजाने की यह एक ऐसी लूट है। जो दिखती नहीं है, लेकिन देश की आर्थिक रीढ़ को लगातार कमजोर कर रही है। रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा संवैधानिक निकाय है। रिजर्व बैंक को सारी दुनिया में मान्यता मिलती है। भारत की बैंकिंग प्रणाली और सरकार की आर्थिक हालात का प्रतिबिंब रिजर्व बैंक है। कारोबार के जरिए तथा विदेशी मुद्रा के नियंत्रण को लेकर जो मुद्रा रिजर्व बैंक पास जमा रहती है। उसी से देश की अर्थव्यवस्था का संचालन भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। जिस तरह से केंद्र सरकार रिजर्व बैंक से डिविडेंड वसूल कर रही है। आगे चलकर आम नागरिकों और कंपनियों से भी सालाना मूल्यांकन करके सरकार इसी तरह का टैक्स वसूल करने की तैयारी तो नहीं कर रही है। अभी तक औद्योगिक संस्थान बैंक से लोन लेने के लिए अपनी संपत्तियों का मूल्यांकन कराकर वित्तीय संस्थानों से लोन लेने के लिए पुर्न मूल्यांकन का उपयोग करते थे। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से रिजर्व बैंक से डिविडेंड वसूल करने के लिए तरह-तरह के उपाय किए जा रहे हैं। अर्थशास्त्रियों के लिए यह चिंता का विषय बन रहा है। एक चिंता यह भी बन रही है, यदि मार्केट में आर्थिक मंदी या और अन्य किसी कारण से बैंकिंग प्रणाली में कोई जोखिम उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में नियामक संस्था के रूप में रिजर्व बैंक कैसे स्थिति से निपटेगा? रिजर्व बैंक में जिस तरह से केंद्र सरकार नियुक्तियां कर रही हैं। अर्थशास्त्रियों का स्थान धीरे-धीरे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दिया जा रहा है। उसके बाद यही सब होना था जो हो रहा है, आगे भगवान ही मालिक है।

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में पीएम मोदी ने की अध्यक्षता, ममता रहीं नदारद

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक का प्रमुख एजेंडा था- 'विकसित राज्य के लिए विकसित भारत एट द रेट 2047'। इस अहम बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसमें भाग नहीं लिया, जिससे एक बार फिर केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव की अटकलें तेज हो गई हैं।

नीती आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में सभी राज्यों से संविधान की भावना के अनुरूप सहकारी संघवाद को आगे बढ़ाने और साझा लक्ष्यों के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आग्रह किया।

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की यह बैठक विकसित भारत एट द रेट 2047 की अवधारणा को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग पर केंद्रित रही। बैठक में 2025-26 के बजट की प्रमुख पहल, आर्थिक विकास की चुनौतियाँ, और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का असर जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। वर्तमान में अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों में आर्थिक सुस्ती के चलते वैश्विक मंदी की आहट देखी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक ने भारत की 2025-26 के लिए विकास दर के अनुमान को घटाकर क्रमशः 6.2 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, नीति आयोग और भारत सरकार का मानना है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.2 प्रतिशत से 6.7 प्रतिशत के दायरे में बनी रह सकती है, जो वैश्विक परिस्थितियों की तुलना में बेहतर मानी जा रही है।

ममता की गैर मौजूदगी का कारण स्पष्ट नहीं

राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक से दूरी बनाने का फैसला किया, लेकिन इसके पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की गई है। यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लिया हो। इससे पहले भी कुछ अवसरों पर उन्होंने अपने विरोध या असहमति का संकेत देने के लिए केंद्रीय बैठकों से दूरी बनाई है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गवर्निंग काउंसिल की बैठक से अनुपस्थित रहे थे। यह दर्शाता है कि नीति आयोग की बैठकों को लेकर राजनीतिक दलों के रुख में विभिन्नता बनी हुई है। डीएमके नेता स्टालिन ने लिया हिस्सा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन बैठक में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही डीएमके नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्टालिन ने दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात की और इसे परिवार के साथ होने जैसा बताया।

संक्षिप्त समाचार

बवाना की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धमाकों से भरभराकर गिरी बिल्डिंग

नई दिल्ली।

बवाना में डीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर-2 में शनिवार तड़के एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इसके बाद एक के बाद एक धमाके होने लगे और थोड़ी ही देर में बिल्डिंग भरभराकर गिर गई। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने से इमारत के अंदर विस्फोट हुआ, जिसके कारण इमारत ढह गई। दमकल की 17 गाड़िया आग बुझाने में जुटी हैं। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है। फैक्ट्री में आग लगने के चलते अंदर से ऊंची-ऊंची लपटें उठती दिखीं और चारों और काले धुएं का गुबार छाने लगा। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही फायर की 17 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग लगने के दौरान इमारत के अंदर हुए कुछ धमाकों के कारण इमारत ढह गई। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली फायर सर्विस चीफ अतुल गर्ग ने बताया, आज सुबह 4.48 बजे आग की सूचना मिलने के बाद सेक्टर-2 में 17 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।

मलकापुर में आरक्षण केन्द्र में जांच के दौरान दो दलाल गिरफ्तार

मुंबई।

सेंट्रल रेलवे ने मलकापुर में आरक्षण केन्द्र (पीआरएस) में जांच के दौरान दो दलालों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सतर्कता दल द्वारा की गई है। जांच के दौरान टीम ने मलकापुर से खरीदे गए 3960 रुपये मूल्य के एसी तत्काल टिकट बरामद किए। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान सरगना संजय चांडक और प्रसाद काले के रूप में हुई। संजय चांडक ने एक मुंबई स्थित दलाल के साथ अपने संबंधों का खुलासा किया, जिसे व्यापक दलाली नेटवर्क के पीछे मास्टरमाइंड माना जाता है। चांडक की पूछताछ में मालूम हुआ कि उसने अवैध रूप से बुक की गई 182 टिकटों की तस्वीरें भेजी थीं, जिनमें 1,61,535/- रुपये की कीमत के 23 टिकट और 8,48,298/- रुपये की कीमत के 159 पुराने टिकट शामिल थे। इस दलाली रैकेट में शामिल दो पकड़े गए व्यक्तियों को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के निरीक्षक को सौंप दिया गया है। रपीएफ मलकापुर द्वारा आगे की जांच की जा रही है।

सीबीएसई ने भाषा को लेकर जारी की गाइडलाइन, स्कूल हर माह देंगे रिपोर्ट

नई दिल्ली।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) के तहत 3 से 11 साल तक के बच्चों की पढ़ाई की भाषा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें सभी स्कूलों से कहा गया है कि वे शैक्षणिक सत्र 2025-26 से बच्चों की पठन पाठन की भाषा को लेकर एनसीएफ में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करें। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे मई अंत तक विद्यालय में एक समिति बनाएंगे जो एनसीएफ लागू करने पर काम करेगी। समिति छात्रों की मातृभाषा, संसाधन और करिकुलम का कार्य करेगी। यह समिति छात्रों की भाषाई जरूरतों का आकलन करेगी और भाषा शिक्षण सामग्री तैयार करवाएगी। नई गाइडलाइन का मकसद सभी छात्रों को उनकी मातृभाषा में मजबूत आधार देना है। नई गाइडलाइन में शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के अलावा यह भी कहा गया है कि स्कूल जुलाई माह से हर महीने की पांच तारीख तक एनसीएफ लागू करने की स्टेट रिपोर्ट बोर्ड को भेजेंगे। रिपोर्ट को लेकर बोर्ड ने एक लिंक भी जारी किया है।सीबीएसई ने कहा कि गर्मियों की छुट्टी के अंत तक विद्यालयों को पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री को तैयार कर लेना चाहिए ताकि आर1 लेंग्वेज का इस्तेमाल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन (दिशानिर्देशों की भाषा) के रूप में किया जा सके। साथ ही सही समय पर बच्चों को आर 2 लेंग्वेज से रूबरू कराया जा सके। इनके लागू किए जाने से पहले शिक्षक को ट्रेनिंग व वर्कशॉप भी पूरी की जानी चाहिए। ट्रेनिंग में बहुभाषी शिक्षण, क्लासरूम स्ट्रेटिजी और भाषा मूल्यांकन पर फोकस किया जाना चाहिए।

न्यायालय की अवहेलना पर आईएएस को हुई एक महीने की सजा, जुर्माना भी लगा

चेन्नई।

करीब 4 दशक पुराने एक मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने आईएएस अंशुल मिश्रा को एक महीने की साधारण सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने उनके वेतन से याचिकाकर्ताओं को 25,000 रुपये का मुआवज़ा देने का भी निर्देश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने सजा पर 30 दिन की राहत दी है ताकि अधिकारी अपील कर सकें। यह मामला वर्ष 1983 से जुड़ा है, जब तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड ने चेन्नई के एक इलाके में याचिकाकर्ता भाई-बहन आर. ललितांबाई और के.एस. विश्वनाथन की 17 सेंट (लगभग 7400 वर्ग फुट) जमीन अधिग्रहित की थी। जमीन पर बहुमंजिला आवास बनाए गए, लेकिन कई दशकों तक वह उपयोग में नहीं लाए गए। याचिकाकर्ताओं ने जमीन के मालिकाना हक की वापसी की मांग करते हुए चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को आवेदन दिया। हाईकोर्ट ने नवंबर 2023 में निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ताओं की मांग पर विचार करते हुए दो महीने के भीतर निर्णय ले। लेकिन विभाग की ओर से इस आदेश का कोई पालन नहीं हुआ। इसके चलते याचिकाकर्ताओं ने अगस्त 2024 में अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की।मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने कहा, यह एक दुखद स्थिति है कि गरीब और पीड़ित लोग अपनी वास्तविक शिकायतों के समाधान के लिए सरकारी विभागों के चक्कर काटते हैं। जब वे अदालत की शरण लेते हैं और अदालत आदेश देती है तब भी अधिकारियों द्वारा उन आदेशों की अवहेलना की जाती है। यह जनता के अधिकारों के साथ अन्याय है और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाता है।कोर्ट ने कहा कि यह कोई एकल घटना नहीं है, बल्कि अधिकारियों द्वारा आदेशों की अनदेखी एक आम प्रवृत्ति बनती जा रही है। ऐसे व्यवहार से न्याय व्यवस्था पर जनता का विश्वास कमजोर होता है। उन्होंने कहा, लोक सेवा कोई विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि जनता द्वारा अधिकारियों पर सौंपी गई एक जिम्मेदारी और भरोसा है।

भारत में आतंकवादी भेजने वाला आज खुद धमाकों से दहल रहा

रिपोर्ट में खुलासा- 2024 में सैकड़ों पाकिस्तानी इन विस्फोटों का हुए शिकार

नई दिल्ली।

पाकिस्तान हाल के दिनों में धमाकों से दहल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान विस्फोटक हथियारों से नागरिकों को नुकसान पहुंचने के मामले में दुनिया का सातवां सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है। एक रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में कुल 790 पाकिस्तानी नागरिक इन विस्फोटों में मारे गए। उस साल वहां 248 ऐसी घटनाएं हुई, जो कि 2023 की तुलना में 11 फीसदी ज्यादा हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन घटनाओं में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) का प्रमुख हाथ है। बीएलए ने अकेले 119 नागरिकों को नुकसान पहुंचाया। बीएलए द्वारा की जाने वाली हिंसा में 440 फीसदी की वृद्धि देखी गई। 2023 में 22 घटनाओं के मुकाबले 2024 में 119 नागरिक ऐसी घटनाओं से प्रभावित हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में हुए सभी आत्मघाती हमलों के पीछे बीएलए ने प्रमुख भूमिका निभाई। 2024 में पाकिस्तान में 2014 के बाद सबसे ज्यादा 248 घटनाएं हुई। 2018 के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऐसी घटनाओं साल रहा जिसमें नागरिकों की ज्यादा मौत हुई। 2015 के बाद दूसरे सबसे ज्यादा

सशस्त्र बल के सदस्य मारे गए। रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों और बीएलए की सक्रियता न केवल स्थानीय शांति के लिए खतरा है, बल्कि क्षेत्रीय अस्थिरता को भी बढ़ावा दे रही है। विशेष रूप से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्रों में बढ़ती हिंसा और आत्मघाती हमलों ने सुरक्षा बलों और आम नागरिकों दोनों को निशाना बनाया है।

साथी को बचाने में खुद जान देने वाले लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी का अयोध्या में बनेगा स्मारक

अयोध्या।

सिक्किम में तैनात अयोध्या के लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने साथी की जान बचाने के लिए खुद के जीवन की परवाह नहीं की। उनका एक साथी अचानक नदी में गिर गया। लेफ्टिनेंट तिवारी ने देखते ही नदी में छलांग लगा दी। नदी की तेज धार में वह तैर नहीं पाए और उनकी जान चली गई। शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अयोध्या में उनका स्मारक बनाया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से उनके परिवार को 50 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। बता दें कि 22 साल के लेफ्टिनेंट तिवारी छह महीने पहले दिसंबर में ही कमीशन हुए थे। उनकी पहली तैनाती सिक्किम स्काउट्स में हुई थी।अयोध्या सिटी मजिस्ट्रेट राजेश मिश्रा ने कहा कि लेफ्टिनेंट तिवारी के पिता जंग बहादुर तिवारी मर्चेंट नेवी में हैं और इस समय अमेरिक में थे। लेफ्टिनेंट तिवारी का पार्थिव शरीर बागडोगरा एयरपोर्ट से सीधा अयोध्या लाया गया था। इसके बाद रातभर पार्थिव शरीर को फैजाबाद मिलिट्री हॉस्पिटल में रखा गया। शुक्रवार देर रात उनका पार्थिव शरीर अयोध्या पहुंचा। शनिवार को जामतारा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेफ्टिनेंट तिवारी अपने मां-बाप के इकलौते बेटे थे। आर्मी की तरफ से कहा गया कि बहुत कम उम्र और सेवा के कम दिनों में ही लेफ्टिनेंट तिवारी ने जो बहादुरी दिखाई है वह सलाम करने लायक है। वह युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने सहयोग की भावना और बहादुरी की मिसाल पेश की है।

भारत में फिर से फैल रहा कोरोना, डॉक्टरों ने यात्रा से बचने और सुरक्षा रखने को कहा

नई दिल्ली।

कोरोना ने फिर से एशियाई देशों और भारत में तेजी से पैर पसार रहा है। हांगकांग, सिंगापुर,थाईलैंड जैसे देशों में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। भारत में भी केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कोविड-19 डैशबोर्ड के मुताबिक 19 मई तक देश में सक्रिय मामलों की संख्या 257 पहुंची है। खासकर केरल में 12 मई से अब तक 69 नए मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं महाराष्ट्र में 44 और तमिलनाडु में 34 नए संक्रमित मिले हैं। इस बढ़ती हुई संख्या ने लोगों में चिंता बढ़ा दी है और ट्रैवल को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन्हें अभी 'चिंता का वेरिएंट' नहीं माना है, लेकिन इसकी तेजी से फैलने की क्षमता ने मोदी सरकारों को सतर्क कर दिया है। इसके चलते निगरानी और टेस्टिंग के उपाय मजबूत किए जा रहे हैं ताकि संक्रमण को रोक सके। हाल के दिनों में इस नई लहर में कुछ चर्चित हस्तियां भी संक्रमित हुई हैं, जिसमें बिग बॉस 18 की

अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर और आईपीएल टीम हैदराबाद के बल्लेबाज ट्रेविस हेड शामिल हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि वायरस अभी भी सक्रिय है और सावधानी बरतना जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान स्थिति में ट्रैवल प्लान करने से पहले दो बार सोचने की जरूरत है, खासकर उन देशों की यात्रा जहां संक्रमण तेजी से फैल रहा है।

डॉक्टरों का कहना हैं कि इम्यूनिटी को मजबूत रखने पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही मास्क पहनना, हाथ धोते रहना और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना बेहद जरूरी है। यात्रा अनिवार्य हो तो इन्हीं सावधानियों का पालन करें ताकि संक्रमण से बचा जा सके। फिलहाल स्थिति देखते हुए, अगर यात्रा टाली जा सके बेहतर होगा।

एनकाउंटर में मारा गया 15 लाख का इनामी जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा

लातेहार।

झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में जेजेएमपी का सुप्रीमो पप्पू लोहरा और उसका एक साथ एनकाउंटर में मारा गया। घटना शनिवार सुबह लातेहार के इचाबार सलैया के जंगलों में हुई है। पप्पू लोहरा पहले नक्सली था। बीते सालों बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों के खात्मे के बाद लोहरा ने अपना अलग संगठन बना लिया था। संगठन बनाने के बाद लोहर अवैध वसूली के साथ-साथ कई अपराधों में शामिल रहा है। पुलिस ने बताया कि जबसे पप्पू ने अपना संगठन बनाया है, उसका गैंग लोगों से लूटपाट करता है। मामला लातेहार के इचाबार सलैया जंगल का है। शनिवार सुबह पुलिस और उग्रवादियों के भीषण मुठभेड़ देखने को मिली। इस मुठभेड़ में झारखंड पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने दो उग्रवादियों को ढेर कर दिया है। इस घटना में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी का सुप्रीमो पप्पू लोहरा भी मारा गया है। मिली जानकारी के अनुसार, पप्पू लोहरा पर कुल 15 लाख रुपए का इनाम था।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी सुप्रीमो पप्पू लोहरा अपने साथियों के साथ लातेहार के इचाबार सलैया जंगल में छिपा है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने जंगल में सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान पुलिस और लोहरा गैंग के बीच भीषण मुठभेड़ देखने को मिली। काफी देर तक चली इस मुठभेड़ में पुलिस के जवानों ने दो नक्सलियों को मार गिराया। जब शव की पहचान की गई तो पता चला कि मारे गए दोनों उग्रवादियों में से एक जेजेएमपी का सुप्रीम लीडर पप्पू लोहरा है। इसके बाद पुलिस के जवानों के चेहरे पर खुशी थी।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों और जवानों के बीच भीषण मुठभेड़ की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीते कुछ महीनों में यहां जवानों ने सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों को मार गिराया है। इसके अलावा हजारों की संख्या में नक्सलियों ने समर्पण भी किया है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ में जवानों ने 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया था।

दिल्ली की फायर सर्विस होगी मजबूत, आग बुझाने की वैश्विक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी

नई दिल्ली।

दिल्ली में आए दिन आग की घटनाएं होती हैं। कई बार तमाम प्रयासों के बाद भी आग बुझाने में लंबा वक्त लग जाता है। ऐसा न हो इसके लिए दिल्ली सरकार आग बुझाने की वैश्विक सुविधाएं मुहैया कराई जाने के लिए प्रयास शुरु हो गए हैं। दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली फायर सर्विसेज का अपग्रेड कर देश विदेश की आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा।सूद ने अग्निशमन सेवा के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद शुक्रवार को कहा कि दिल्ली फायर सेवा ने आधुनिक तकनीक से लैस करने के साथ ही फायर ब्रिगेड की नई गाड़ियों की खरीद पर निर्णय लिया जा रहा है। इसमें कुछ गाड़ियां विदेशी तकनीक और कुछ गाड़ी स्वदेशी तकनीक से लैस होंगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली फायर सर्विस को आधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए फायर ब्रिगेड के बेड़े में 17 नए वाटर बाउजर, 4 एरियल वाटर टावर और 24 नए क्विक रिस्पांस वीकल शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड के बेड़े में कई रोबोटिक वाहन भी शामिल किए गए हैं। उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि जैसे-जैसे दिल्ली की जनसंख्या बढ़ रही है वैसे-वैसे ही हमें आग पर काबू पाने के लिए नई तकनीक का प्रयोग करना होगा। दिल्ली की तंग गलियों से लेकर भीड़ भाड़ वाले बाजारों के लिए छोटी गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी जोर देना होगा ताकि आग लगने की घटना होने पर तुरंत घटनास्थल पर गाड़ियां पहुंच सकें। सूद ने कहा कि अग्निकांड जैसे हादसा होने पर त्वरित कार्रवाई करने की भी योजना बनाने की जरूरत है, ताकि दुर्घटना होने पर जल्द से जल्द लोगों को बचाया जा सके। सूद ने बताया कि बैठक में दिल्ली फायर सर्विस को स्टेट ऑफ दी आर्ट सर्विस बनाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। इस संबंध में निदेशक फायर सर्विस को कहा गया है कि देश के विभिन्न राज्यों की फायर सर्विस प्रणाली का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि उस राज्य की नई-नई तकनीकों को

दिल्ली फायर सर्विस में लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि फायर सर्विस निदेशक अगले 15 से 20 साल की योजना और बढ़ती हुई आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनाएं।

चाईबासा कोर्ट के गैर-जमानती वारंट से राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्किलें

26 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश

रांची।

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है और उन्हें 26 जून 2025 को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।

यह वारंट राहुल गांधी की लगातार अनुपस्थिति और अदालत द्वारा जारी समन की अवहेलना के चलते जारी किया गया। राहुल गांधी के वकील द्वारा दाखिल व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी को न्यायिक दंडाधिकारी ने खारिज कर दिया। इससे पहले भी उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए।

मामला किससे जुड़ा है?

यह पूरा मामला 28 मार्च 2018 को दिए गए एक राजनीतिक भाषण से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इस भाषण के बाद भाजपा नेता प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

इस मुकदमे को झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर फरवरी 2020 में रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। बाद में चाईबासा में जब एमपी-एमएलए कोर्ट की शुरुआत हुई तो मामला पुनः वहीं स्थानांतरित कर दिया गया।

तय समय से 8 दिन पहले केरल पहुंचा मानसून...

16 साल पहले 2009 में 9 दिन पहले आया था मानसून... 4 जून तक मप्र पहुंचने की संभावना

- भारत में मानसून ने दी दस्तक...
- दिल्ली-नोएडा, मुंबई समेत कई बड़े शहरों में भी ऑरेंज अलर्ट

नई दिल्ली।

मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। यह भारत की मुख्य भूमि पर पिछले 16 वर्षों में मानसून का सबसे पहले आगमन है। इस बार अपने तय वक्त से 8 दिन पहले ही मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। भारत के मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। पिछली बार राज्य में मानसून इतनी जल्दी 2009 और 2001 में आया था, जब यह 23 मई को राज्य में पहुंचा था। केरल में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। हालांकि, 1918 में राज्य में 11 मई को ही मानसून ने दस्तक दे दी थी, जो आज तक का केरल में सबसे जल्दी मानसून आगमन का इकलौता मामला है।

दूसरी ओर, मानसून के देरी से केरल आगमन का रिकॉर्ड 1972 में दर्ज है, जब मानसून की बारिश 18 जून को शुरू हुई थी। पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक देरी से मानसून का आगमन 2016 में हुआ, जब मानसून ने 9 जून को केरल में प्रवेश किया। आईएमडी ने मानसून के आगमन को देखते हुए केरल के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है- जो अगले 24 घंटों में 20 सेमी से अधिक बारिश का सामना कर सकते हैं। कुछ अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जहां 11 सेमी से 20 सेमी के बीच बारिश हो सकती है। आईएमडी ने 6 सेमी से 11 सेमी के बीच भारी बारिश की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

कई जगह बौछारें पड़ने का अनुमान

दिल्ली के आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने एक बयान में कहा कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में 25 और 26 मई को गरज-चमक के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। 27 मई को बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इससे पहले 21 मई की शाम को दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भयंकर तूफान आया था। 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं और बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई थी।

मुंबई में भारी वर्षा का अनुमान

दक्षिण कोंकण, गोवा तट के पास और पूर्व मध्य अरब सागर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके चलते आईएमडी ने अगले तीन दिनों के लिए कोंकण क्षेत्र में अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने एक बयान में कहा कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिले के लिए अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना का पूर्वानुमान लगाते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मुंबई, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग के साथ-साथ पुणे और सतारा के लिए भारी बारिश, गरज और तेज हवाओं के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी से बहुत भारी वर्षा, गरज के साथ छींटे पड़ने और अलग-अलग स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है।

कृषि क्षेत्र को होगा फायदा

मानसून के जल्दी आने से आमतौर पर सभी क्षेत्रों में सकारात्मक भावनाएं आती हैं, विशेषकर कृषि क्षेत्र में, जो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। समय पर बारिश होने से भूजल स्तर में सुधार होता है, जलाशय भरते हैं, तथा धान, दलहन, तिलहन, कपास और सब्जियों जैसी खरीफ फसलों की शीघ्र बुवाई में मदद मिलती है- ये सभी खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आय के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, मौसम विशेषज्ञों ने पहले ही आगाह कर दिया था कि मानसून की शुरुआत उत्साहजनक है, लेकिन वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले हफ्तों में देश भर में मानसून कितनी स्थिरता और एकरूपता से आगे बढ़ता है। सफल खरीफ सीजन सुनिश्चित करने के लिए मानसून का पूरे देश में एक समान प्रसार और बारिश होना आवश्यक है। असमान वर्षा या लंबे समय तक सूखा पड़ने से मानसून के जल्दी शुरू होने के लाभ समाप्त हो सकते हैं।

पठानकोट के खेत में मिला मोर्टार

पठानकोट।

पठानकोट के सोली भोली गांव के एक खेत में मोर्टार मिलने से लोगों में दहशत फैल गई। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक ग्रामीण ने बम जैसी वस्तु देखी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बम जैसी वस्तु को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इसकी सूचना सेना को भी दी और सेना की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर जिंदा मोर्टार को निष्क्रिय कर दिया। इस दौरान गांव के सरपंच भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक यह मोर्टार बीर सिंह नाम के व्यक्ति के खेत में देखा गया था और उसके बाद ही पुलिस को इसकी सूचना दी गई।

मोहाली में पुलिस ने दबोचे 7 नाइजीरियन

चंडीगढ़।

मोहाली में पंजाब पुलिस ने 7 नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये एक किराए के मकान में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को ठगते थे। इन्होंने अश्लील चैट दिखा कर शादीशुदा व्यक्तियों को ब्लैकमेल कर 15 करोड़ रुपए ठगे थे। पुलिस ने क्रह्मस् की धारा 318(4), 61(2) और आईटी एक्ट की धारा 66 में मामला दर्ज किया है। इनके कब्जे से करीब 2.10 करोड़ रुपए कीमत का सामान बरामद किया गया है। मोहाली के एसएसपी हरमनदीप हंस ने कहा कि आरोपियों को डीएसपी रुपिंदरदीप कौर सोही की सुपरविजन में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी खुद को फेसबुक पर कभी पायलट तो कभी इंजीनियर बताते थे।

3 भाइयों की गोली मारकर हत्या

बक्सर।

बक्सर में शनिवार की सुबह दो पक्षों में झड़प के बाद अंधाधुंध फायरिंग हुई। इस गोलीबारी में 5 लोगों को गोली लगी है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं, दो गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वाले सभी भाई हैं। जो जख्मी हैं, वो भी मृतकों के भाई हैं। फायरिंग के बाद 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वारदात का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दो गुटों में पहले लाठी-डंडे और पत्थरबाजी हो रही है। इसके बाद दूसरे गुट के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक मिनट के वीडियो में 12 बार गोली चलने की आवाज सुनाई दे रही है। घटना राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव में नहर किनारे की है। बताया जा रहा है कि बालू कारोबार को लेकर हुई लड़ाई के बाद बदमाशों ने गोलियां चलाई है।

भारत-नेपाल सीमा पर पकड़ा गया संदिग्ध

बहराइच(ईएमएस)।

यूपी के बहराइच में शुक्रवार की रात भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। उसकी भाषा काफी अजीब है। जो स्थानीय निवासियों से काफी अलग है। एसएसबी ने उसे पुलिस को सौंप दिया है। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उससे पूछताछ की जाएगी। मामला मोतीपुर क्षेत्र का है। यहां भारत-नेपाल सीमा पर एक युवक घूम रहा था। एसएसबी जवानों को शंका हुई तो उसे रोका। उससे बातचीत करके उसका पता और टहलने का कारण पूछा। इस पर उसने जिस भाषा में जवाब दिया, वह पहले तो किसी को समझ में ही नहीं आई। इस पर शक और गहरा गया।

केंद्र और सभी राज्य टीम इंडिया की तरह काम करें, तब लक्ष्य असंभव नहीं : पीएम मोदी

नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक

नई दिल्ली।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शनिवार को हुई। बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बैठक को संबोधित कर पीएमए मोदी ने कहा कि हमें विकास की गति को बढ़ाना है। अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें, तब लक्ष्य असंभव नहीं है।

पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा, भारत भी विकसित होगा। यह 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। उन्होंने कहा कि राज्यों को वैश्विक मानकों के अनुरूप सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करके प्रत्येक राज्य में करीब एक पर्यटन स्थल को तैयार करना चाहिए। एक राज्य-एक वैश्विक गंतव्य। इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। उन्होंने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ यह पहली बड़ी बैठक है। बयान के अनुसार, विकसित भारत के लिए विकसित राज्य का विचार राज्यों से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जुड़े साहसिक, दीर्घकालिक और समावेशी विजन दस्तावेज तैयार करने का आह्वान है, जो स्थानीय वास्तविकताओं पर आधारित हों। इन विजनों में समयबद्ध लक्ष्य शामिल

होने चाहिए। आम तौर पर, पूर्ण परिषद की बैठक हर साल होती है और पिछले साल यह 27 जुलाई को हुई थी।

लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाला गिरफ्तार

नई दिल्ली।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों को फर्जी पासपोर्ट के साथ देश से भागने में मदद करने वाले एक प्रमुख सहयोगी को गिरफ्तार किया है। एनआईए अधिकारियों ने बताया कि गिरोह के पासपोर्ट मॉड्यूल को चलाने वाले राहुल सरकार को गिरफ्तार किया है। एनआईए अधिकारियों ने बताया कि राहुल सरकार को मामले की जांच के लिए पटियाला हाउस स्थित एजेंसी की विशेष अदालत ने एनआईए की हिरासत में भेज दिया। एनआईए ने पाया कि आरोपी गिरोह के सदस्यों के लिए जाली पासपोर्ट की व्यवस्था करता था, इससे आरोपियों को अपराध करने के बाद देश से भागने में मदद मिलती थी। जांच एजेंसी द्वारा जारी बयान के अनुसार, गिरोह के जिन सदस्यों की राहुल सरकार ने मदद की थी, इसमें सचिन थापन उर्फ सचिन थापन बिश्नोई भी शामिल है, जो 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मुख्य आरोपी है।

मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा तैयार करें

भारत के चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश

नई दिल्ली।

मतदान दिवस की गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के मकसद से एक महत्वपूर्ण कदम उठाकर, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मतदाताओं के लिए मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा को बेहतर और मतदान केंद्रों के पास प्रचार मानदंडों को तर्कसंगत बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

ये कदम कानूनी अनिवार्यताओं का पालन कर चुनावी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने के आयोग के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं। ईसीआई ने निर्देश दिया है कि मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा स्थापित करे। नए दिशा-निर्देशों के तहत, मतदाताओं को मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार के पास रखे गए साधारण पिजनहोल बॉक्स या जूट बैग में अपने मोबाइल फोन जमा करना होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर मोबाइल फोन को बंद कर देना चाहिए और मोबाइल अंदर नहीं ले जाना चाहिए।

हालांकि, रिटर्निंग अधिकारियों को स्थानीय चुनौतियों के मद्देनजर कुछ मतदान केंद्रों को नियम से छूट देने का अधिकार दिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49एम, जो मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करता है, का सख्ती से पालन किया जाता रहेगा। चुनाव के दिन रसद बढ़ाने की एक समानांतर पहल में, आयोग ने प्रचार के लिए अनुमेय मानदंडों को भी युक्तिसंगत बनाया है। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के 100 मीटर के दायरे में अब चुनाव प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह मतदान स्थल के करीब मतदाताओं पर किसी भी तरह के प्रभाव के खिलाफ एक सख्त रुख को दर्शाता है। अनौपचारिक मतदाता पहचान पर्चियां देने वाले अभियान बूथ अब केवल 100 मीटर की सीमा से आगे ही स्थापित हो सकते हैं, जिससे कम दखलंदाजी और अधिक व्यवस्थित मतदान वातावरण सुनिश्चित होगा।

ये उपाय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव संचालन नियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप हैं। वे मतदाता सुविधा को चुनावी कानून के सख्त पालन के साथ संतुलित करने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

टेक सपोर्ट घोटाले के आरोपी अंगद सिंह अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित

नई दिल्ली।

टेक सपोर्ट घोटाले के आरोपी अंगद सिंह चंडोक को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया है। चंडोक को एक अमेरिकी अदालत ने ऑनलाइन टेक सपोर्ट घोटाला चलाने के लिए दोषी माना था, इससे अमेरिकी नागरिकों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों से लाखों डॉलर की ठगी की गई थी। आरोपों के अनुसार, चंडोक ने कई फर्जी कंपनियां बनाकर उनका इस्तेमाल टेक सपोर्ट स्कीम के दवारा चुराए गए फंड को भारत और दूसरे देशों में ट्रांसफर करने के लिए किया। अमेरिकी न्याय विभाग ने मार्च 2022 में जारी बयान में आरोपी चंडोक की घोटाले में संलिप्तता के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें अमेरिकी वरिष्ठ नागरिकों को धोखाधड़ी से निशाना बनाने की बात कही गई। सीबीआई ने चंडोक को अमेरिका से प्रत्यर्पित करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। उसके प्रत्यर्पण के बाद, भारत की एक अदालत में पेश किया जाएगा, जहां एजेंसी द्वारा उसकी हिरासत की मांग किए जाने की उम्मीद है।

चाईबासा कोर्ट के गैर-जमानती वारंट से राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्किलें

26 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश

रांची। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है और उन्हें 26 जून 2025 को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। यह वारंट राहुल गांधी की लगातार अनुपस्थिति और अदालत द्वारा जारी समन की अवहेलना के चलते जारी किया गया। राहुल गांधी के वकील द्वारा दाखिल व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी को न्यायिक दंडाधिकारी ने खारिज कर दिया। इससे पहले भी उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए।

मामला किससे जुड़ा है?

यह पूरा मामला 28 मार्च 2018 को दिए गए एक राजनीतिक भाषण से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इस भाषण के बाद भाजपा नेता प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे को झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर फरवरी 2020 में रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। बाद में चाईबासा में जब एमपी-एमएलए कोर्ट की शुरुआत हुई तो मामला पुनः वहीं स्थानांतरित कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को कैडर समीक्षा को लेकर दिए निर्देश

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 2021 में होने वाली कैडर समीक्षा को 6 माह की अवधि के अंदर आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी सहित सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में किया जाए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को कैडर समीक्षा और मौजूदा सेवा/भर्ती नियमों के संशोधन के संबंध में गृह मंत्रालय से कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त होने के तीन माह के भीतर उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया। यह निर्देश गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन, कैडर समीक्षा, पुनर्गठन और आईपीएस प्रतिनियुक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से भर्ती नियमों में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं के समूह की सुनवाई के दौरान जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि सीएपीएफ के कैडर अधिकारियों की सेवा गतिशीलता के दोहरे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर एक ओर ठहराव को दूर करना और दूसरी ओर बलों की परिचालन/ कार्यात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि सीएपीएफ के कैडर में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) के स्तर तक प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित पदों की संख्या को समय के साथ उत्तरोत्तर कम किया जाना चाहिए।

इससे सीएपीएफ के प्रशासनिक ढांचे के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीएपीएफ से संबंधित कैडर अधिकारियों की भागीदारी की भावना आएगी, जिससे कैडर अधिकारियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतें दूर होंगी। पीठ ने सीमाओं पर और देश के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने में सीएपीएफ की आवश्यक भूमिका पर जोर दिया।

एपल भारत में ही बनाएगी आईफोन

कंपनी अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में नहीं आएगी, ट्रम्प चाहते हैं अमेरिका में बनें फोन

नई दिल्ली ।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की धमकी के बाद भी एपल भारत में ही आईफोन बनाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में आईफोन के प्रोडक्ट्स से कंपनी को काफी फायदा होगा। इसीलिए कंपनी किसी राजनीतिक दबाव में कोई फैसला नहीं लेगी।

मामले से जुड़े एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बताया कि, उन्हें पूरा विश्वास है कि एपल ट्रम्प प्रशासन के किसी भी दबाव के बावजूद कंपनी मुनाफे को तब्ज्जो देगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी भारत में उपलब्ध टेलेंट और यहां बिजनेस के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है।

ट्रम्प ने 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया

डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा था कि अमेरिका में बेचे जाने वाले आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत या किसी अन्य देश में नहीं, बल्कि अमेरिका में ही होना चाहिए। उन्होंने एपल के सीईओ टिम कुक को बता दिया है कि यदि एपल अमेरिका में आईफोन नहीं बनाएगा तो कंपनी पर कम से कम 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया जाएगा।

अभी भारत में बन रहे 15 प्रतिशत आईफोन

फिलहाल एपल अमेरिका में स्मार्टफोन नहीं बनाती है। इसके ज्यादा तक आईफोन चीन में बनाए जाते हैं, जबकि भारत में अब एपल के कुल उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा बनता है, जो सालाना लगभग 40 मिलियन यूनिट है।

वहीं एपल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही दिए एक इंटरव्यू में

बताया था कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50प्रतिशत आईफोन भारत में बन रहे हैं। कुक ने कहा कि भारत अप्रैल-जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। उन्होंने बताया कि एयरपॉड्स, एपल वॉच जैसे अन्य प्रोडक्ट्स भी ज्यादातर वियतनाम में बनाए जा रहे हैं।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। मो. नं. 9928078717